

[2025] 4 एस.सी.आर 71 : 2025 आईएनएससी 349

प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1314/2025)

17 मार्च 2025

[विक्रम नाथ* और प्रसन्न बी. वराले, जे. जे.]

विचार के लिए मुद्दा

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों के एक मामले में अपीलकर्ता के उन्मोचन आवेदन को अस्वीकार करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

मुख्य बिंदु

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप यह था कि वह अपराध की आय से संबंधित वित्तीय लेन-देन में शामिल था, जो राज्य को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पहुँचाने वाली धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न हुई थी। अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया है कि कथित कार्य पीएमएलए के तहत कोई अपराध नहीं बनाते हैं क्योंकि वे प्रासंगिक अवधि के दौरान लागू नहीं थे, या कथित मूल अपराध प्रासंगिक समय पर पीएमएलए की अनुसूची में शामिल नहीं थे, और इसलिए, वे पीएमएलए के तहत कार्यवाही का विषय नहीं हो सकते हैं।

अभिनिर्धारित: यह तर्क अमान्य है - यह सुस्थापित है कि पीएमएलए के तहत अपराध निरंतर प्रकृति के होते हैं, और धन शोधन का कार्य किसी एक ही घटना के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि तब तक जारी रहता है जब तक अपराध के आगम को छुपाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, या बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पीएमएलए के पीछे विधायी उद्देश्य धन शोधन के खतरे से लड़ना है, जो अपने आप में समय के साथ फैली लेनदेन को शामिल करता है- वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह स्थापित करती है कि अपीलकर्ता द्वारा शक्ति

* लेखक

और पद के दुरुपयोग, अपराध के आगम के कथित उपयोग और छिपाव के साथ मिलकर एक स्थायी प्रभाव पड़ा है। धन शोधन का कार्य केवल एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब तक जारी रहती है जब तक आपराधिक गतिविधि से प्राप्त लाभ वित्तीय प्रणाली के भीतर चलन में रहते हैं या आरोपी द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे होते हैं। प्रतिवादी ने यह प्रस्तुत किया है कि अपराध की आय के उपयोग के नए मामले हाल के समय में भी सामने आए हैं, जिससे यह अपराध वर्तमान तक फैला हुआ है और अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज करता है कि यह कार्य अतीत के एक विशेष बिंदु तक ही सीमित था। प्रतिवादी ने प्रथमदृष्टया सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि अपीलकर्ता अपराध की आय से जुड़े वित्तीय लेनदेन में शामिल रहा है जो कमीशन के प्रारंभिक बिंदु से परे है -जहाँ तक पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू करने की सांविधिक सीमा का संबंध है, वित्तीय निशान इंगित करता है कि कथित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त परिसंपत्तियों का कुल मूल्य निर्धारित सीमा से काफी अधिक है। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री, पीएमएलए के व्यापक विधायी ढांचे के साथ मिलकर, यह इंगित करती है कि विचारण को आगे बढ़ने देना आवश्यक है और आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में अपीलकर्ता को उन्मोचित नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 21,24,25,26,27,34]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-निरंतर अपराध:

अभिनिर्धारित: पीएमएलए के तहत निरंतर अपराध की अवधारणा न्यायिक मिसालों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित की गई है -एक अपराध को तब निरंतर माना जाता है जब अवैध कार्य या उसके परिणाम समय के साथ बने रहते हैं, जिससे अपराधी की देयता बढ़ जाती है। पीएमएलए की धारा 3 धन शोधनके अपराध को परिभाषित करती है जिसमें अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने, जानबूझकर सहायता करने, जानबूझकर एक पक्ष बनने, या वास्तव में शामिल होने के प्रयास शामिल हैं। यदि ऐसी भागीदारी लंबे समय तक चलती है, तो यह एक निरंतर अपराध का गठन करती है। [पैरा 22]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002- उद्देश्य:

अभिनिर्धारित: पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और अपराध की आय को जब्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के अवैध धन वित्तीय प्रणाली को कमजोर न करें-मनी लॉन्ड्रिंग के दूरगामी परिणाम हैं, न केवल भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत कृत्यों

के मामले में बल्कि सरकारी खजाने को भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते हैं- अपराध की आय के धनशोधन के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण नुकसान होता है, वैध वित्तीय लेनदेन बाधित होते हैं, और प्रणाली में जनता का विश्वास कम होता है।[पैरा 30]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-प्रारंभिक चरण में न्यायिक हस्तक्षेप:

अभिनिर्धारित: अवैध रूप से धन का उपयोग करने और उसे अलग करने का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान होता है और निवेश और वित्तीय संसाधनों के वैध क्षेत्रों को वंचित किया जाता है-यह सुस्थापित कानून है कि गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में, प्रारंभिक स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, और बाध्यकारी कानूनी आधारों की अनुपस्थिति में कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए - प्रतिवादी ने सही तर्क दिया है कि इस तरह के परिमाण के आरोपों से जुड़े मामलों में, गलत काम की पूरी सीमा स्थापित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण/ट्रायल अनिवार्य है-पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में अपराध की आय के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था -वित्तीय अपराधों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, अदालतों को आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में एक सख्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधी न्याय से बचने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों का फायदा न उठाएं।[पैरा 31,32]

उद्धृत वाद कानून

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [2022] 6 एससीआर 382:(2023) 12 एस. सी. सी. 1- दर्भित।
ईडी बनाम मेसर्स ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, दाण्डिक अपीलीय सं 1269/2017-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002।

मुख्य शब्दों की सूची

अपराध का आगम; अपराध के आगम को छिपाना; धोखाधड़ी की गतिविधियाँ; राज्य को वित्तीय नुकसान; धन शोधन; निर्वहन; मूल अपराध; सांविधिक सीमा;

न्यायिक हस्तक्षेप; निरंतर अपराध; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227; आर्थिक अपराध; प्रारंभिक चरण; अवैध वित्तीय लेनदेन; सरकारी खजाने को नुकसान।

वाद उत्पत्ति

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:दाण्डिक अपीलीय सं 1314/2025

सीआरएलआरए संख्या 66/2018 में अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.03.2023 के निर्णय और आदेश से

पक्षों की उपस्थिति

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता:

कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अल्जो के. जोसेफ, विनय कुमार पुववाला, संतोष कुमार कोलकोंडा, साकेत जी।

प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता:

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, कानू अग्रवाल, विवेक गुरनानी, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, सुश्री नेहा सिंह।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

विक्रम नाथ, जे.

1. अवकाश अनुदत्त।
2. वर्तमान अपील गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पारित उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002¹ के तहत अपराधों के एक मामले में अपीलकर्ता के उन्मोचन आवेदन को अस्वीकार करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
3. अपीलकर्ता ने आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 66/2018 द्वारा उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें पीएमएलए वाद संख्या 02/2016 में विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 08.01.2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी। विशेष न्यायाधीश ने पीएमएलए के तहत दर्ज मामले से मुक्ति की मांग करने वाले, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973² की धारा 227 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर उन्मोचन आवेदन को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता को पीएमएलए के तहत सूचीबद्ध अपराधों से उत्पन्न धन शोधन के आरोपों के आधार पर इसमें फँसाया गया था।

4. अपीलकर्ता के विरुद्ध यह मामला एक कथित आर्थिक अपराध से उत्पन्न हुआ है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 - प्रवर्तन निदेशालय³ ने पीएमएलए के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की थी। मुख्य आरोप यह था कि अपीलकर्ता उन वित्तीय लेनदेन में शामिल था जो 'अपराध की आय' से संबंधित थे। यह आय धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न की गई थी, जिससे गुजरात राज्य को महत्वपूर्ण वित्तीय हानि हुई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए बैंकिंग चैनलों और अन्य वित्तीय साधनों का उपयोग करके धन शोधन की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से सुगम बनाया था।
5. अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दर्ज इसीआईआर/01/एजीओ/2012 के अनुसरण में की गई जाँच के संबंध में 31.07.2016 को गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 12.03.2012 की यह प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट⁴ दिनांक 31.03.2010 की प्राथमिकी संख्या 03/2010 और दिनांक 25.09.2010 की प्राथमिकी संख्या 09/2010 के अनुसरण में दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए 27.09.2016 को विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक शिकायत दर्ज की। वर्तमान मामले में, दो प्राथमिकियों के अनुसार दो सूचीबद्ध अपराध थे:
 - i. आई-सीआर संख्या 03/2010: जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988⁵ की धारा 7, 11, 13(1)(B), 13(2) के तहत अपराधों के लिए राजकोट जोन, सीआईडी क्राइम में दर्ज की गई थी; और
 - ii. आई-सीआर संख्या 09/2010: जो भारतीय दंड संहिता की धारा 217, 409, 465, 467, 468, 471, 476, 120-B के तहत अपराधों के लिए राजकोट जोन, सीआईडी क्राइम में दर्ज की गई थी।
6. इन दोनों मामलों में संबंधित अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। उच्च न्यायालय के दिनांक 03.02.2012 के आदेश को आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ता पहले अनुसूचित अपराध में अग्रिम जमानत पर है। दूसरे सूचीबद्ध अपराध में, अपीलकर्ता इस न्यायालय के दिनांक 13.12.2011 के आदेश के अनुसरण में नियमित जमानत पर है।
7. अपीलकर्ता ने पीएमएलए मामले में आरोपमुक्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 227 के तहत विशेष न्यायाधीश से इस आधार पर संपर्क किया कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और पीएमएलए के तहत कोई अपराध नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता को 06.01.2010 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 08.01.2010

को निलंबित कर दिया गया था, जिस अवधि के दौरान उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी और इसलिए अब उनके सेवा में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपराध कथित रूप से तब किए गए थे जब पीएमएलए लागू नहीं था और इस प्रकार इन प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। उनका यह तर्क था कि उनके विरुद्ध आरोपित लेन-देन उस कंपनी के थे जिसमें उनकी पत्नी भागीदार हैं और इसलिए इन्हें उनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका के बैंक में उनके द्वारा धारित खातों में किए गए लेन-देन को किसी भी अपराध के अनुसरण में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वे खाते वहाँ अपनी पढ़ाई के दौरान खोले थे और उन खातों का उपयोग उसी अवधि के लेन-देन के लिए किया गया था।

8. विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) ने दिनांक 08.01.2018 के अपने निर्णय में यह अवलोकन किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा की गई जाँच के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता 'हवाला' अर्थात् विदेशों में धन के अवैध हस्तांतरण में संलिप्त है, वह अपराध की आय/आगम पर कब्जा रखने वाला भी प्रतीत होता है, और प्रथम दृष्टया उन अपराधों में संलिप्त प्रतीत होता है जिनसे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभिलेख की सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता प्रथमदृष्टया हवाला में करोड़ों रुपये के लेन-देन में भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय की राय में, अपीलकर्ता पीएमएलए की धारा 24 के तहत सबूत के बोझ का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहा है, जो यह दिखाने के लिए उस पर स्थानांतरित हो गया था कि अपराध की आय एक बेदाग संपत्ति है। विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) की राय में, इतने गंभीर मामले में अपीलकर्ता की संलिप्तता का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद थी, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उन्मोचित करने से इनकार कर दिया, और इसके साथ ही सी.आर.पी.सी. की धारा 227 के तहत उसके आवेदन को खारिज कर दिया।
9. व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने विशेष न्यायाधीश के उपरोक्त फैसले को रद्द करने और रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उसके खिलाफ आरोप निराधार हैं और पीएमएलए के तहत अपराध नहीं हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ कथित अनुसूचित अपराध

पीएमएलए में धन शोधन प्रावधानों की शुरुआत से पहले के थे, और इसलिए, वर्तमान मामले में मांगे गए पीएमएलए का आवेदन पूर्वव्यापी था और इस प्रकार कानून में अस्वीकार्य था। उसे अपराध की आय के सृजन, कब्जे, छिपाने या हस्तांतरण से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था।

10. आगे यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि आरोप विशुद्ध रूप से धारणाओं और अनुमानों पर आधारित थे। विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के विरुद्ध पुख्ता सामग्री के अभाव पर उचित विचार किए बिना उसके उन्मोचन आवेदन को खारिज करने में त्रुटि की है। प्रवर्तन कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से, ठोस साक्ष्य के अभाव के बावजूद, केवल उसे परेशान करने के इरादे से शुरू की गई थी।
11. राज्य और प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता धन शोधन की संपूर्ण योजना में एक मुख्य सूत्रधार था और उसने धन को बेदाग के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कई लेन-देन के माध्यम से उसके 'लेयरिंग' और 'प्लेसमेंट' की सुविधा प्रदान की थी।
12. यह भी तर्क दिया गया कि जाँच में यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सामग्री का खुलासा हुआ था कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर धन शोधन गतिविधियों में सहायता की थी और अपराध की आय से वित्तीय लाभ प्राप्त किया था।
13. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पीएमएलए के भूतलक्षी प्रभाव के संबंध में अपीलकर्ता का तर्क अनुचित था, क्योंकि धन शोधन का अपराध एक निरंतर जारी रहने वाला अपराध है, और जब तक दूषित धन संचलन में रहता है, तब तक पीएमएलए लागू रहता है। विशेष न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का परीक्षण किया था और अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार पाए थे, जिससे उसके उन्मोचन आवेदन को खारिज किया जाना न्यायोचित था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को, अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित आदेशों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई प्रत्यक्ष त्रुटि या न्याय की विफलता न हुई हो, जो कि इस मामले में नहीं थी।
14. उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.03.2024 के विवादित आदेश के माध्यम से आपराधिक संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे अपीलार्थी के आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री कथित

अपराध में अपीलकर्ता की प्रथमदृष्टया संलिप्तता का संकेत देती है। उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि, आरोप पत्र और आरोप तय करने के चरण में विचार किए जाने वाले दस्तावेजों के आलोक में, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में जाए बिना, विचारण न्यायालय का आदेश किसी भी अवैधता, अनियमितता या अनुचितता से ग्रस्त नहीं है।

15. उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता या कानूनी दुर्बलता नहीं पाई, जो इसके पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप की गारंटी देता है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रकृति के आर्थिक अपराधों के लिए एक सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, और अदालतों को शुरुआती चरण में कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। इन निष्कर्षों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी के आरोपमुक्त आवेदन की अस्वीकृति उचित थी और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया।
16. उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित अपीलकर्ता ने अब फैसले की शुद्धता को चुनौती देने के लिए अपील में इस न्यायालय का रुख किया है।
17. हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को विस्तार से सुना है।
18. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:
 - 18.1 कथित विधेय अपराध, जो कथित रूप से अपराध की आय उत्पन्न करते थे, पीएमएलए के लागू होने से पहले हुए थे। इसके अतिरिक्त, ये अपराध पी. एम. एल. ए. (संशोधन) अधिनियम, 2009 से पहले के हैं। परिणामस्वरूप, ऐसी कार्रवाइयाँ पीएमएलए की धारा 2(1)(u) में यथा-परिभाषित 'अपराध की आय' उत्पन्न नहीं कर सकती थीं, जो यह निर्धारित करती है कि किसी संपत्ति को केवल तभी अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त हुई हो। इस तर्क की पुष्टि के लिए, अपीलकर्ता ने पीएमएलए के प्रवर्तन और विभिन्न संशोधनों का एक विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया है। पीएमएलए 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ, और विभिन्न आधारभूत अपराधों को अलग-अलग तिथियों पर इसकी अनुसूची में शामिल किया गया था। प्रारंभ में, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम, 1988 को पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के रूप में शामिल नहीं किया गया था। आईपीसी की धारा 467 मूल रूप से पीएमएलए अनुसूची (भाग ख) का हिस्सा थी, लेकिन केवल तभी जब ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य तीस लाख रुपये या उससे अधिक था। बाद में, 1 जून 2009 को आईपीसी की धारा 420 को पीएमएलए अनुसूची के भाग B में जोड़ा गया, जिसमें समान मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई थी। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 को 1 जून 2009 से पीएमएलए अनुसूची के भाग ख में शामिल किया गया था, जो पुनः केवल तभी लागू था जब अपराध में तीस लाख रुपये से अधिक की राशि शामिल हो। तत्पश्चात, पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से, जो 4 जनवरी 2013 से प्रभावी हुआ, आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 467 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 को पीएमएलए अनुसूची के भाग क में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे किसी भी मौद्रिक सीमा को हटा दिया गया।

(18.2) यह उपधारा मामले के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक मोड़ को दर्शाती है, जहाँ प्रवर्तन निदेशालय ने **विजया मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ⁶** के ऐतिहासिक निर्णय का सहारा लिया है। हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि इस निर्णय में भूतलक्षी प्रभाव से निपटने वाले एकमात्र पैराग्राफ 270 और 296 हैं, जबकि इस मुद्दे पर विस्तृत दलीलें पेश की गई थीं। निर्णय में केवल यह माना गया है कि "एक दी गई तथ्यात्मक स्थिति में," पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध को एक निरंतर जारी रहने वाला अपराध माना जा सकता है, भले ही अनुसूचित अपराध कभी भी किया गया हो। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि इस निर्णय के पैराग्राफ 467 के निष्कर्ष भूतलक्षी प्रभाव के मुद्दे का समाधान नहीं करते हैं। वर्तमान में, इस न्यायालय की एक तीन- न्यायाधीशों की पीठ प्रवर्तन निदेशालय बनाम मेसर्स ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (क्रिमिनल अपील संख्या 1269/2017) और संबंधित मामलों में पीएमएलए तथा इसके संशोधनों के भूतलक्षी प्रभाव पर विचार-विमर्श कर रही है।

18.3 अपीलकर्ता का आगे यह तर्क है कि आठ आधारभूत अपराध की प्राथमिक सूचना रिपोर्टों में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से उन कार्रवाइयों से संबंधित हैं, जो अभियुक्त ने भुज और राजकोट में कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से की थीं। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2004 और 2005 में

निजी कंपनियों और व्यक्तियों को अपनी अधिकृत शक्तियों से बाहर जाकर बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन को मंजूरी दी, जिससे आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध कारित किए गए। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए कृषि से औद्योगिक भूमि उपयोग के परिवर्तन को जल्दबाजी में मंजूरी दी, जिससे आईपीसी की धारा 420 और 467 के तहत अपराध कारित किए गए। इसके अतिरिक्त, कथित तौर पर उन्होंने 2004 और 2005 में बाजार दरों से कम पर भूमि आवंटन की सुविधा प्रदान की, जिससे सरकार को काल्पनिक हानि हुई, जो आईपीसी की धारा 420 और 467 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, कथित तौर पर 2004 और 2009 के बीच कुछ निजी कंपनियों ने उनके मोबाइल फोन के बिलों का भुगतान किया, जो कुल मिलाकर लगभग ₹2.24 लाख और ₹46,554/- थे, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत रिश्वतखोरी के रूप में वर्णित किया गया है। यह दलील दी गई है कि ये सभी कथित कृत्य या तो पीएमएलए के लागू होने से पहले हुए थे, या उस समय हुए थे जब आईपीसी की धारा 420 और 467 'आधारभूत अपराध' की श्रेणी में शामिल नहीं थे।

18.4 इन आरोपों पर पीएमएलए की अनुप्रयोज्यता को रेखांकित करने और उजागर करने के लिए, अपीलकर्ता द्वारा कथित कृत्यों और प्रासंगिक समय पर पीएमएलए के लागू होने का एक कालानुक्रमिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था।

अवधि	आधारभूत अपराध की प्राथमिक सूचना रिपोर्टों में लगाए गए आरोप	लागू होने वाला कानून
01.07.2005 से पहले	i. यह आरोप लगाया गया है कि भुज में कलेक्टर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, जो 02.05.2003 से शुरू हुआ था, अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, वे 1997 की एक भू-राजस्व नीति [परिपत्र दिनांक 25.09.1997] के प्रभारी थे, जिसने निजी व्यक्तियों को परती भूमि आवंटित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने नीति के विपरीत ऐसी भूमि आवंटित की और सरकार के साथ धोखाधड़ी की, हानि पहुँचाई, इन आवंटन अनुरोधों के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने की अनुमति देकर जालसाजी की और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे।	पीएमएलए लागू नहीं।

	ii. भुज में भूकंप से प्रभावित लोगों को भूमि आवंटन के लिए गुजरात सरकार के 03.02.2002 के आदेश के अनुसार, यह सत्यापित करने के लिए कलेक्टर से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी कि पीड़ित वास्तव में भूकंप से प्रभावित हुआ था। अभियुक्तों ने क्षतिपूर्ति भूमि के लिए अपने धोखाधड़ी वाले आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ट्रस्ट को एक नकली प्रमाण पत्र प्रदान किया। iii. गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के संकल्प संख्या जामन/392003/454/A दिनांक 06.06.2003 के अनुसार, कलेक्टर को केवल औद्योगिक उपयोग के लिए 2 हेक्टेयर तक की भूमि आवंटित करने के लिए अधिकृत किया गया था। iv. जब अभियुक्त प्रदीप शर्मा भुज के कलेक्टर थे, तब उन्होंने एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स साँ पाइप्स लिमिटेड को परती भूमि के आवंटन की अनुमति दी थी। ये आवेदन 23.01.2004 को प्रस्तुत किए गए थे और 05.03.2004 को इन्हें मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अभियुक्त प्रदीप ने 05.03.2004 को 2 हेक्टेयर की निर्धारित सीमा से अधिक भूमि आवंटन का आदेश जारी किया। v. अभियुक्त प्रदीप को मेसर्स वेलस्पन कंपनी के निदेशक असीम निरंजन चक्रवर्ती से एक मोबाइल सिम कार्ड संख्या 9925133799 प्राप्त हुआ था, जिसके लिए कंपनी द्वारा 2004-2009 की अवधि के दौरान ₹ 2.24 लाख के बिल का भुगतान किया गया था। यह कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 11 और 13 के तहत दंडनीय रिश्त थी, क्योंकि यह वर्ष 2004 में मेसर्स वेलस्पन को कथित रूप से कम मूल्य पर भूमि आवंटन के बदले में दी गई थी।	
--	---	--

	vi. मेसर्स वेलस्पन को 22.07.2004 को ₹30/- प्रति वर्ग मीटर के बजाय ₹15/- प्रति वर्ग मीटर की दर से किए गए इन कम मूल्य वाले आवंटनों के कारण सरकार को ₹1,20,30,824/- की वित्तीय हानि हुई। मेसर्स वैल्यू पैकेजिंग नामक कंपनी द्वारा 01.02.2005 को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें अभियुक्त प्रदीप की पत्नी एक भागीदार हैं। यह आवेदन भूमि को कृषि से गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने के लिए किया गया था। अभियुक्त प्रदीप ने 10.03.2005 को एक आदेश पारित करके 40 दिनों के भीतर इसकी अनुमति दे दी, जो आईपीसी की धारा 217, 409, 465, 467, 471, 476 और 120-ख के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। Vii अभियुक्त प्रदीप को मेसर्स रतन एंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक रंजीत सिंह भक्तसिंह भट से मोबाइल सिम कार्ड संख्या 9824001729 प्राप्त हुआ और उन्होंने इसका उपयोग किया। 2004-2009 की अवधि के लिए ₹46,554/- के बिल का भुगतान श्री भट द्वारा किया गया था, जिसे कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/11/13 के तहत दंडनीय रिश्वत माना गया है।	
01.07.2005 और 01.06.2009 के बीच	i. यह आरोप लगाया गया है कि भुज में कलेक्टर के रूप में उनके कार्यकाल (02.05.2003 से 03.07.2006) और उसके बाद राजकोट में (28.03.2008 तक) अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, वे 1997 की एक भू-राजस्व नीति [परिपत्र दिनांक 25.09.1997] के प्रभारी थे, जो निजी व्यक्तियों को परती भूमि के आवंटन की अनुमति देती थी। उन्होंने नीति के विरुद्ध	पीएमएलए लागू धारा 420 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मूल रूप से

	जाकर ऐसी भूमि आवंटित की और सरकार के साथ धोखाधड़ी की, राजस्व की हानि पहुँचाई, इन आवंटन अनुरोधों के लिए फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति देकर जालसाजी की और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। ii. जब अभियुक्त प्रदीप भुज के कलेक्टर थे, तब उन्हें 18.07.2005 को चंदन मंडली नामक व्यक्ति का एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें सरकार से उसे मिली भूमि के पट्टे के विस्तार का अनुरोध किया गया था; इस आवेदन को शुरुआत में अभियुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय, 2005 में किए गए आवेदनों के माध्यम से 30 इकाइयों का आवंटन किया गया, भले ही यह 2 हेक्टेयर की निर्धारित सीमा को पार कर गया था। iii. जब अभियुक्त प्रदीप राजकोट के कलेक्टर थे, तब उन्होंने 23.05.2007 को एक आदेश पारित कर उन आवेदकों को कृषि भूमि का आवंटन बहाल कर दिया जो विदेश में रह रहे थे, जबकि वे इसके लिए अपात्र थे। iv. अभियुक्त प्रदीप को मेसर्स वेलस्पन कंपनी के निदेशक असीम निरंजन चक्रवर्ती से एक मोबाइल सिम कार्ड संख्या 9925133799 प्राप्त हुआ था, जिसके लिए कंपनी द्वारा 2004-2009 की अवधि के दौरान ₹2.24 लाख के बिल का भुगतान किया गया था। यह कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/11/13 के तहत दंडनीय रिश्तत थी, क्योंकि यह वर्ष	अनुसूचित अपराध नहीं थे।
--	---	--------------------------------

	2004 में मेसर्स वेलस्पन को कथित रूप से कम मूल्य पर भूमि आवंटन के बदले में दी गई थी। v. अभियुक्त प्रदीप को मेसर्स रतन एंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक रंजीत सिंह भक्तसिंह भट से मोबाइल सिम कार्ड संख्या 9824001729 प्राप्त हुआ और उन्होंने इसका उपयोग किया। 2004-2009 की अवधि के लिए ₹46,554/- के बिल का भुगतान श्री भट द्वारा किया गया था, जिसे कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/11/13 के तहत दंडनीय रिश्वत माना गया है। vi. अप्रैल 2009 में साझेदारी से सेवानिवृत्त होने पर, उनकी पत्नी को मेसर्स वैल्यू पैकेजिंग से बैंक ऑफ इंडिया में स्थित उनके एनआरओ बैंक खाते में ₹22 लाख प्राप्त हुए। उनके ₹1,50,000/- के मूल निवेश को घटाने के बाद, यह राशि ₹20.5 लाख के लाभ के बराबर थी, जिसे कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/11/13 के तहत दंडनीय रिश्वत माना गया। vii. प्रदीप शर्मा की पत्नी को मेसर्स वैल्यू पैकेजिंग से 'गुडविल पेमेंट' के रूप में ₹7.5 लाख प्राप्त हुए, जिसे कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/11/13 के तहत दंडनीय रिश्वत माना गया।	
01.06.2009 और 04.01.2013	i. अभियुक्त प्रदीप को मेसर्स वेलस्पन कंपनी के निदेशक असीम निरंजन चक्रवर्ती से एक मोबाइल सिम कार्ड संख्या 9925133799 प्राप्त	पीएमएलए को पीएमएलए (संशोधन)

के बीच	हुआ था, जिसके लिए कंपनी द्वारा 2004-2009 की अवधि के दौरान ₹2.24 लाख के बिल का भुगतान किया गया था। यह वर्ष 2004 में वेलस्पन को कथित तौर पर कम मूल्य पर भूमि आवंटन के बदले में था, जो कथित रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/11/13 के तहत दंडनीय रिश्त थी। ii. अभियुक्त प्रदीप को मेसर्स रतन एंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक रंजीत सिंह भक्तसिंह भट से मोबाइल सिम कार्ड संख्या 9824001729 प्राप्त हुआ और उन्होंने इसका उपयोग किया; 2004-2009 की अवधि के लिए ₹46,554/- के बिल का भुगतान श्री भट द्वारा किया गया था, जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/11/13 के तहत दंडनीय रिश्त थी। iii. अभियुक्त प्रदीप को पालोरा जेल में हिरासत में रहते हुए एक सिम कार्ड मिला क्योंकि एक विचाराधीन अपराध केवल तभी बनाया गया था जब ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य तीस लाख या उससे अधिक हो।	अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 01.06.2009 को प्रभावी हुआ: आईपीसी की धारा 420/467 और पीसी एक्ट (PC Act) की धारा 13 को पीएमएलए की अनुसूची (भाग ख) में रखा गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि अपराध केवल तभी माना जाएगा जब ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य ₹30 लाख या उससे अधिक हो।
04.01.2013 से	कोई आरोप नहीं	पीएमएलए लागू आईपीसी की धारा 420/467 और भ्रष्टाचार

		निवारण अधिनियम की धारा 13 को पीएमएलए की अनुसूची (भाग ए) में शामिल किया गया था, जिसमें कोई न्यूनतम मौद्रिक मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया गया था।
--	--	---

18.5 इस प्रकार, उपरोक्त आरोपों के आधार पर, पीएमएलए के आवेदन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईं:

- क. 1 जुलाई 2005 से पहले, पीएमएलए लागू नहीं था। 2 मई 2003 को भुज में कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, आरोपी 1997 से एक भूमि राजस्व नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने निजी संस्थाओं को परती भूमि के आवंटन की अनुमति दी थी। यह आरोप लगाया जाता है कि उसने नियमों के विपरीत भूमि आवंटन को मंजूरी देने के लिए इस नीति का दुरुपयोग किया, जिससे उसने धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के अपराध किए। 3 फरवरी 2002 के गुजरात सरकार के आदेश के तहत, भूकंप पीड़ितों को भूमि आवंटन के लिए कलेक्टर से उनकी पात्रता को सत्यापित करने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आरोपी ने कथित तौर पर एक ट्रस्ट को धोखाधड़ी का प्रमाण पत्र जारी किया, जिससे गलत तरीके से भूमि आवंटन की सुविधा मिली। इसके अलावा, गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के 6 जून 2003 के प्रस्ताव ने कलेक्टर को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दो हेक्टेयर तक की भूमि आवंटित करने के लिए अधिकृत किया था। हालांकि, यह आरोप है कि 2004 में, उन्होंने मेसर्स साँ पाइप्स लिमिटेड और मेसर्स वेलस्पन कंपनी को काफी कम दरों पर भूमि के बड़े हिस्से आवंटित करके

इस सीमा का उल्लंघन किया, जिससे सरकार को ₹1,20,30,824/- की वित्तीय हानि हुई। इसके अतिरिक्त, उनकी पत्नी मेसर्स वैल्यू पैकेजिंग में भागीदार थीं, जिसने 2005 में भूमि-उपयोग रूपांतरण के लिए आवेदन किया था, और उन्होंने कथित तौर पर 40 दिनों के भीतर मंजूरी की सुविधा प्रदान की, जिसमें 217,409,465,467,471,476 और 120-ख सहित कई आईपीसी धाराओं के तहत अपराध शामिल थे।

- ख. 1 जुलाई 2005 और 1 जून 2009 के बीच, जब पीएमएलए लागू था, आईपीसी की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अनुसूचित अपराध नहीं थे; हालांकि, आईपीसी की धारा 467 को अनुसूची के 'भाग ख' में शामिल किया गया था, जो केवल तभी लागू होती थी जब अपराध में शामिल मूल्य तीस लाख रुपये से अधिक हो। इस अवधि के दौरान, अभियुक्तों के खिलाफ इसी तरह के आरोप जारी रहे, जिनमें भुज और राजकोट में अनुचित भूमि आवंटन, कृषि भूमि के लिए अयोग्य आवेदनों की मंजूरी और कथित रिश्वत के और मामले शामिल थे। विशेष रूप से, इस अवधि के दौरान, उनकी पत्नी को अप्रैल 2009 में साझेदारी से सेवानिवृत्त होने पर मेसर्स वैल्यू पैकेजिंग से अपने एनआरओ बैंक खाते में 22 लाख रुपये प्राप्त हुए। ₹1.50 लाख के उनके मूल निवेश में कटौती करने के बाद, शेष ₹20.5 लाख कथित रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक अवैध लाभ था। इसके अतिरिक्त, उन्हें सद्भावना भुगतान के रूप में 7.5 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसे अधिनियम के तहत रिश्वत भी माना जाता था।
- ग. 1 जून 2009 से 4 जनवरी 2013 तक, पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2009 प्रभावी था, जिसने आईपीसी की धारा 420 और 467 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 को पीएमएलए अनुसूची (भाग ख) में पुनः तीस लाख रुपये की मौद्रिक सीमा के साथ जोड़ा। इस दौरान, आरोपी कथित तौर पर पिछली भूमि आवंटन के बदले में कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए मोबाइल फोन बिलों से लाभान्वित होते रहे। इसके अलावा, यह आरोप लगाया जाता है कि एक विचाराधीन कैदी के रूप में पलोरा जेल में हिरासत में रहते हुए, उसने एक सिम कार्ड प्राप्त किया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह पीएमएलए के तहत अपराध है या नहीं।

घ. अंत में, 4 जनवरी 2013 से, पीएमएलए में आईपीसी की धारा 420 और 467 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 को अपनी अनुसूची के भाग ए में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, जिससे किसी भी न्यूनतम मौद्रिक सीमा को हटा दिया गया। हालाँकि, इस अवधि के दौरान की गई कार्रवाई के लिए अभियुक्तों के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।

18.6 उपरोक्त समय सीमा के आलोक में किया गया प्राथमिक निवेदन यह है कि आरोप मुख्य रूप से पीएमएलए लागू होने से पहले या उस अवधि के दौरान किए गए कार्यों से संबंधित हैं जब संबंधित अपराध अधिनियम के तहत निर्धारित नहीं थे। यह आगे तर्क दिया गया है कि कानूनी ढांचे और पीएमएलए के पिछली तिथि से लागू होने के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष लंबित विचार-विमर्श को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पर उन कथित आधारभूत अपराधों के लिए पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो इसके अधिनियमन से पहले या पीएमएलए अनुसूची में उन अपराधों के शामिल होने से पहले घटित हुए थे।

19. विद्वान महान्यायवादी ने प्रतिवादी अधिकारियों और राज्य की ओर से निम्नलिखित निवेदन किया है:

19.1 प्रतिवादी तर्क देता है कि पीएमएलए के पिछली तिथि से लागू होने के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक 'निरंतर जारी रहने वाला अपराध' है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, और इसे मामले के तथ्यों के आधार पर सही ढंग से लागू किया गया है।

19.2 प्रतिवादी इस बात पर जोर देता है कि आरोप तय करने के चरण में, अदालत को केवल यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या अपराध किए जाने का "गंभीर संदेह" पैदा करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इस स्तर पर साक्ष्य के संभावित मूल्य का आकलन नहीं किया जाता है, और यदि प्रथमदृष्टया अपराध पाया जाता है तो मामले को मुकदमे के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

19.3 प्रतिवादी प्रस्तुत करता है कि धन शोधन मामले का आधार बनने वाले विधेय अपराध संबंधित समय पर पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध थे। विशेष रूप से, आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आने वाले आधारभूत अपराध उनके किए जाने के समय पहले से ही पीएमएलए की अनुसूची

में शामिल थे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, वर्ष 2005 में मूल रूप से अधिनियमित पीएमएलए अनुसूची के भाग ख (भाग ख), पैरा 5 का हिस्सा थी। आईपीसी की धारा 467/2005 में अधिनियमित पीएमएलए अनुसूची के भाग ख, पैरा 1 का हिस्सा थी। कथित अपराध का कुल मूल्य ₹30 लाख से अधिक था, जिसने 'भाग ख' के अपराध के लिए पीएमएलए की धारा 2(1)(y) के तहत निर्धारित मौद्रिक सीमा को पूरा किया। 2009 और 2013 में पीएमएलए में संशोधनों ने केवल धन शोधन अपराधों के दायरे का विस्तार किया, लेकिन इस मामले में पूर्वव्यापी दायित्व की शुरुआत नहीं की।

19.4 प्रतिवादी ने यह स्थापित करने के लिए एक विस्तृत तथ्यात्मक समयरेखा प्रदान की कि अपराध पीएमएलए लागू होने के बाद किया गया था। प्राथमिकी संख्या 3/2010 को 31.03.2010 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज किया गया था, जो कि 01.07.2005 से ही पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध रहा है। इसी तरह, FIR संख्या 9/2010 को 25.09.2010 को आईपीसी की धारा 467 के तहत दर्ज किया गया था, जो कि 01.07.2005 से ही पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध रहा है। इसके अतिरिक्त, अवैध भूमि आवंटन के लिए मंजूरी आदेश अपीलकर्ता द्वारा 09.06.2006 को जारी किया गया था, जो पीएमएलए के लागू होने के बाद भी आपराधिक आचरण की निरंतरता को स्थापित करता है। 2011 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के तहत दायर आरोप पत्र ने पुष्टि की कि अपराध की कुल आय ₹1.32 करोड़ से अधिक थी, जो पीएमएलए को लागू करने को उचित ठहराती है।

19.5 प्रतिवादी ने यह दावा किया कि अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से लॉन्ड्रिंग की गई राशि ₹30 लाख की उस सीमा से कहीं अधिक है, जो 2013 के संशोधन से पहले 'भाग ख' के अनुसूचित अपराध के लिए आवश्यक थी। आरोप पत्र यह दर्ज करता है कि सरकार को हुआ कुल नुकसान ₹1.20 करोड़ था, जो अपने आप में ही निर्धारित सीमा से अधिक है। इसके अलावा, जांच और पीएमएलए की धारा 5 के तहत कुर्की की कार्यवाही के माध्यम से यह पहचान की गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई अपराध की कुल आय ₹1.32 करोड़ है। अभियुक्त ने कथित तौर पर अपनी पत्नी द्वारा प्राप्त ₹22 लाख को एक व्यावसायिक इकाई से प्राप्त लाभ के रूप में दर्शाया, जो वास्तविकता में अवैध परितोषण को छिपाने का एक प्रयास

था। अभियुक्त से जुड़े कई हवाला लेनदेन में ₹1 करोड़ से अधिक की राशियाँ शामिल थीं, जो इस वित्तीय अपराध की व्यापकता को और पुष्टा करती हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मामला पीएमएलए के दायरे में है, यहां तक कि पूर्व-संशोधन कानूनी ढांचे के तहत भी।

19.6 प्रतिवादी ने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक स्वतंत्र और निरंतर जारी रहने वाला अपराध है, और यह केवल उस तारीख तक सीमित नहीं है जब आधारभूत अपराध किया गया था। ईडी **विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त)** मामले में इस अदालत के फैसले पर निर्भर करता है, जिसमें कहा गया था कि धन शोधन का अपराध केवल निर्धारित अपराध से परे है। अपराध की आय से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया या गतिविधि, जिसमें कब्ज़ा, उपयोग, छिपाना, या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करना शामिल है, पीएमएलए के तहत निरंतर दायित्व को आकर्षित करती है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि वह होती है जब अभियुक्त 'अपराध की आय' से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होता है, न कि वह तारीख जब आधारभूत अपराध किया गया था। 2019 में पीएमएलए की धारा 3 में संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक था और इसमें नई देनदारियों को शामिल नहीं किया गया था।

19.7 प्रतिवादी ने अपीलार्थी के इस दावे का खंडन किया कि इस मामले में पीएमएलए को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता ने 2005 के काफी समय बाद तक अपराध की आय का आनंद लेना और उसका उपयोग करना जारी रखा, जिससे पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध लागू होता है। भूमि आवंटन के लिए मंजूरी आदेश 2006 में पारित किए गए थे, यानी पीएमएलए के लागू होने के बाद, और ये फर्जी दस्तावेजों पर आधारित थे, जो अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध का गठन करते हैं। पीएमएलए की धारा 24 के तहत सबूत का उल्टा बोझ अपीलकर्ता पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालता है कि कुर्क की गई संपत्तियां अपराध की आय नहीं थीं, जो वह करने में विफल रहा है।

19.8 प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने में कानून को सही ढंग से लागू किया। अनुसूचित अपराध उनके किए जाने के समय पीएमएलए की अनुसूची का हिस्सा थे, और मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध पीएमएलए के लागू होने के काफी समय बाद तक निरंतर जारी रहा। इसके अतिरिक्त, इसमें शामिल कुल राशि ₹30 लाख की उस

सीमा से कहीं अधिक है, जो संशोधन से पहले अनुसूची के 'भाग ख' के तहत आवश्यक थी। इसलिए, पूर्वव्यापी आवेदन के संबंध में अपीलार्थी का तर्क गलत है और योग्यता विहीन है।

20. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, अभिलेख पर सामग्री और पीएमएलए के तहत वैधानिक ढांचे पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय को अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है।
21. अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण आधार पीएमएलए के तहत कथित अपराध की प्रकृति से संबंधित है। अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया है कि कथित कृत्य पीएमएलए के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि प्रासंगिक अवधि के दौरान यह कानून प्रभावी नहीं था। साथ ही, यह भी तर्क दिया गया है कि कथित आधारभूत अपराध उस समय पीएमएलए की अनुसूची में शामिल नहीं थे, और इसलिए पीएमएलए के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि ये घटनाएं निरंतर जारी रहने वाले अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। हालाँकि, यह तर्क असमर्थनीय है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पीएमएलए के तहत अपराध एक निरंतर प्रकृति के हैं, और धन शोधन का कार्य एक भी उदाहरण के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि तब तक चलता है जब तक कि अपराध की आय को छुपाया जाता है, उपयोग किया जाता है, या बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया जाता है। पीएमएलए के पीछे विधायी मंशा मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटना है, जिसमें अपनी प्रकृति के कारण ही ऐसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो एक लंबी समयावधि तक चलती हैं।
22. पीएमएलए के तहत निरंतर जारी रहने वाले अपराध की अवधारणा न्यायिक पूर्व निर्णय द्वारा सुस्थापित की जा चुकी है। एक अपराध को तब जारी माना जाता है जब अवैध कार्य या उसके परिणाम समय के साथ बने रहते हैं, जिससे अपराधी का दायित्व बढ़ जाता है। पीएमएलए की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें 'अपराध की आय' से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करना, जानबूझकर सहायता करना, जानबूझकर पक्षकार बनना, या वास्तव में शामिल होना शामिल है। इस तरह की संलिप्तता, यदि लंबे समय तक चलती है, तो एक निरंतर अपराध है।
23. भले ही पीएमएलए के पूर्वव्यापी आवेदन का मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, **विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा)** में इस न्यायालय के अवलोकन पर प्रतिवादी द्वारा निर्भरता को गलत नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने इस मामले

में अपने फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और निरंतर अपराध के रूप में इसकी प्रकृति के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"134. 2002 के अधिनियम की धारा 3 की स्पष्ट भाषा से यह पूरी तरह साफ है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध 'अपराध की आय' से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है, जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई हो।" प्रक्रिया या गतिविधि किसी भी रूप में हो सकती है—चाहे वह छिपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने, अपराध की आय का उपयोग करने के लिए हो, जितना कि इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या ऐसा होने का दावा करना। इस प्रकार, अपराध की आय से जुड़ी ऐसी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना धन शोधन का अपराध होगा। यह अपराध (मनी लॉन्ड्रिंग), अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से अन्यथा कोई सरोकार नहीं रखता है — सिवाय उस अपराध की आय के, जो उस अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त या हासिल की गई हो।

135. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि केवल आपराधिक गतिविधि (एक अनुसूचित अपराध) के परिणामस्वरूप संपत्ति प्राप्त होने या प्राप्त होने के बाद ही की जा सकती है। अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना या सहायता करना या पक्षकार होना मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध होगा और किसी तथ्य की स्थिति में ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर अपराध हो सकता है, चाहे अनुसूचित अपराध की तारीख और समय कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में, भले ही आपराधिक गतिविधि उस समय की गई हो जब उसे 2002 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए 'अनुसूचित अपराध' के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस आपराधिक गतिविधि से प्राप्त अपराध की आय के लेन-देन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है या शामिल रहना जारी रखता है—भले ही वह अधिसूचना के बाद ही क्यों न हो—तो वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए उत्तरदायी हो सकता है। यह उत्तरदायित्व अपराध की आय को कब्जे में रखने, छिपाने, या उसे किशतों में तब तक उपयोग करने के लिए बनता है जब तक कि वह पूरी तरह समाप्त न हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का

अपराध उस तारीख पर निर्भर या उससे जुड़ा नहीं है, जिस दिन अनुसूचित अपराध या जिसे हम आधारभूत अपराध कह सकते हैं, किया गया था। प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस पर व्यक्ति अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है। ये घटक मूल प्रावधान (धारा 3, जैसा कि 2013 तक संशोधित किया गया था और 31-7-2019 तक प्रभावी था) में अंतर्निहित हैं; और 2019 के वित्त (संख्या 2) अधिनियम द्वारा स्पष्टीकरण के माध्यम से इन्हें केवल व्याख्यायित और स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार समझा जाता है कि 2019 में अंतःस्थापित स्पष्टीकरण में खंड (ii) को शामिल करने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि यह धारा 3 के दायरे को बिल्कुल भी नहीं बदलता है या विस्तारित नहीं करता है।

[बल दिया गया]

24. वर्तमान मामले में, अभिलेख की सामग्री यह स्थापित करती है कि अपीलकर्ता द्वारा शक्ति और पद का दुरुपयोग, अपराध की आय के कथित उपयोग और छिपाने के साथ, एक स्थायी प्रभाव पड़ा है। धन शोधन का कार्य एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब तक जारी रहती है जब तक कि आपराधिक गतिविधि से प्राप्त लाभ वित्तीय प्रणाली के भीतर प्रचलन में रहते हैं या अभियुक्त द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। प्रतिवादी ने यह प्रस्तुत किया है कि अपराध की आय के उपयोग के नए उदाहरण हाल के समय में भी सामने आए हैं, जिससे यह अपराध वर्तमान समय तक विस्तृत हो गया है। यह तथ्य अपीलकर्ता के उस तर्क को पूरी तरह खारिज करता है कि यह कृत्य अतीत के किसी एक विशिष्ट समय तक ही सीमित था।
25. कानून यह मान्यता देता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कोई स्थिर घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है, जब तक कि अवैध लाभ पर कब्ज़ा बना रहता है, उसे वैध के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या उसे फिर से अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। इस प्रकार, यह तर्क कि अपराध जारी नहीं है, कानून या तथ्यों के आधार पर अच्छा नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। भले ही वर्तमान मामले के संदर्भ में जांच की जाए, अपीलार्थी का तर्क संधार्य नहीं है। अभिलेख पर सामग्री अपीलकर्ता द्वारा शक्ति और पद के निरंतर और बार-बार दुरुपयोग का संकेत देती है, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्तारित अवधि में अपराध की आय का उत्पादन और उपयोग होता है। प्रतिवादी ने प्रथम दृष्टया

सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित किया है कि अपीलकर्ता अपराध की शुरुआत के बाद भी 'अपराध की आय' से जुड़े वित्तीय लेनदेन में शामिल रहा। ऐसी आय का उपयोग, कथित लेयरिंग और इंटीग्रेशन, तथा ऐसे फंडों को बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करने के प्रयास, ये सभी पीएमएलए के तहत एक निरंतर जारी रहने वाले अपराध के तत्व हैं। अतः, अपीलकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से कानूनी ढांचे के भीतर है और इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

26. अपीलकर्ता द्वारा दी गई एक अन्य दलील यह है कि इसमें शामिल राशि पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए उस वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करती है, जैसा कि संशोधन से पहले के कानून में प्रावधान था। अपीलकर्ता ने इस तर्क के समर्थन में ₹30 लाख की मौद्रिक सीमा का सहारा लिया है कि प्रासंगिक समय पर, यह अपराध पीएमएलए के प्रावधानों के दायरे में नहीं आता था। यह तर्क भी समान रूप से "योग्यता विहीन" है।
27. प्रतिवादी ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है जो यह प्रदर्शित करती है कि अपराध की आय की कुल मात्रा वैधानिक सीमा से काफी अधिक है। वित्तीय लेनदेन इंगित करता है कि कथित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त परिसंपत्तियों का कुल मूल्य निर्धारित सीमा से काफी अधिक है। यह तय किया गया कानून है कि सीमा मूल्य का निर्धारण लेन-देन की संपूर्णता पर आधारित होना चाहिए न कि किसी अलग उदाहरण या किसी भी समय विशिष्ट राशियों की संकीर्ण व्याख्या पर।
28. प्रतिवादी ने श्रेणीबद्ध रूप से यह स्थापित किया है कि विचाराधीन राशि पीएमएलए के बिना संशोधित प्रावधानों के तहत भी ₹30 लाख की सीमा से कहीं अधिक है। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों में जालसाजी, धोखाधड़ी, और छल के माध्यम से की गई भूमि आवंटन लेनदेन शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹1 करोड़ से अधिक का कथित नुकसान हुआ है। इसके साथ ही, करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन और उनकी पत्नी के माध्यम से लगभग ₹22 लाख की अवैध रिश्वत के आरोप भी शामिल हैं। कथित कृत्यों में वित्तीय लेन-देन, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, अपराध की आय की काफी अधिक राशि को प्रकट करता है, जिससे अपीलार्थी की सीमा पर निर्भरता आधारहीन हो जाती है।
29. इसके अलावा, यह तय किया गया कानून है कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल राशि के निर्धारण को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि समग्र वित्तीय लेनदेन और संबंधित लेनदेन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। साक्ष्यों की समग्रता का आकलन किया

जाना चाहिए, जो कि मुकदमे/ट्रायल का विषय है; लेकिन प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में 'अपराध की आय' वैधानिक सीमा से काफी अधिक है। अपीलकर्ता इस संबंध में प्रत्यर्थी की दलीलों का खंडन करने वाली किसी भी सामग्री के साथ अपने दावे को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, यह आधार भी किसी भी तरह से अपीलकर्ता के लिए सहायक नहीं है।

30. पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और अपराध की आय को जब्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अवैध फंड वित्तीय प्रणाली को कमजोर न करें। मनी लॉन्ड्रिंग के दूरगामी परिणाम हैं, न केवल भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत कृत्यों के संदर्भ में, बल्कि सरकारी खजाने को भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाने में। अपराध की आय के धनशोधन के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है, वैध वित्तीय लेनदेन बाधित होता है और प्रणाली में जनता का विश्वास कम होता है। वर्तमान मामले में कथित अपराधों का अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अवैध वित्तीय लेनदेन राज्य को वैध राजस्व से वंचित करते हैं, बाजार की अखंडता को विकृत करते हैं और आर्थिक अस्थिरता में योगदान करते हैं। इस तरह के कार्य, जब सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, तो शासन में जनता के विश्वास को कम करते हैं और वित्तीय संस्थानों के भीतर प्रणालीगत कमजोरियों का कारण बनते हैं।
31. अवैध रूप से धन का उपयोग करने और उसे अलग करने का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान होता है और वैध क्षेत्रों को निवेश और वित्तीय संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है। यह तय किया गया कानून है कि गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में, प्रारंभिक स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, और बाध्यकारी कानूनी आधारों की अनुपस्थिति में कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने सही तर्क दिया है कि इस तरह के परिमाण के आरोपों से जुड़े मामलों में, गलत काम की पूरी सीमा स्थापित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण अनिवार्य है।
32. पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में अपराध की आय के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था। वित्तीय अपराधों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, अदालतों को आर्थिक अपराधों से संबंधित

मामलों में एक सख्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधी न्याय से बचने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों का फायदा न उठाएं।

33. वर्तमान मामले में वित्तीय कदाचार, पद का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का गठन करने वाले लेनदेन में शामिल होने के गंभीर आरोप शामिल हैं। अपीलकर्ता प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को समाप्त करने की मांग करता है, जिससे सक्षम मंच के समक्ष तथ्यों और साक्ष्य के पूर्ण निर्णय को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। हालाँकि, जैसा कि कई न्यायिक घोषणाओं में स्थापित किया गया है, आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में घटनाओं की पूरी श्रृंखला, वित्तीय लेनदेन और अभियुक्त की दोषसिद्धि का पता लगाने के लिए एक गहन परीक्षण की आवश्यकता होती है।
34. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री, पीएमएलए के व्यापक विधायी ढांचे के साथ मिलकर, मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति देने की आवश्यकता को इंगित करती है और आरोप निर्धारण के प्रारंभिक चरण में अपीलकर्ता को आरोपमुक्त नहीं करती है। यह तर्क कि कार्यवाही अनुचित है, तथ्यहीन है, विशेष रूप से कानून के वैधानिक उद्देश्यों, अपराध की निरंतर प्रकृति, और कथित कृत्यों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों के आलोक में। अपीलकर्ता को इस स्तर पर कार्यमुक्त करना समयपूर्व होगा और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अभियोजन के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के विपरीत होगा।
35. अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों की गंभीर और संगीन प्रकृति को देखते हुए, यह अनिवार्य है कि उसे मुकदमे के दौरान गहन न्यायिक जांच से गुजरना होगा। अपराध के पूर्ण विस्तार को उजागर करने, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने, अंतिम लेनदेन की पूरी श्रृंखला का विश्लेषण करने और गंभीर आरोपों की सच्चाई तथा 'अपराध की आय' की वास्तविक राशि का पता लगाने के लिए एक उचित मुकदमा आवश्यक है। पीएमएलए के तहत कानूनी ढांचा एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्तियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए और आर्थिक अपराध बिना सजा के न छूटें।
36. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता मुकदमे से पहले के चरण पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य कोई भी कानूनी रूप से टिकाऊ आधार स्थापित करने में विफल रहा है। अपील के समर्थन में दी गई दलीलें न तो कानूनी रूप से मान्य हैं और न ही न्याय के सर्वोत्तम हित में हैं। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध स्पष्ट रूप से पीएमएलए के तहत एक 'निरंतर अपराध' है, और इसमें शामिल

'अपराध की आय' की मात्रा वैधानिक सीमा से कहीं अधिक है, जिसके लिए उचित जांच और न्यायिक जांच आवश्यक है। निचली अदालतों के निष्कर्ष सुसंगत और तर्कसंगत हैं और उनमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

37. परिणामस्वरूप, याचिका खारिज कर दी जाती है।

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

वाद का परिणाम: याचिका खारिज कर दी गई।

मुख्य बिंदु अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किए गए

1 पीएमएलए

2 सीआरपीसी

3 ईडी

4 ईसीआईआर

5 पीसी अधिनियम

6 (2023) 12 एससीसी 1